International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

औद्योगिक क्रान्ति के भारत पर राजनीतिक प्रभाव

Jyoti
MA in History, MDU Rohtak
Reg. No. 04-MKR-110
Email : siwacharya@gmail.com

औद्योगिक क्रांति एक ऐसा शब्द जिसने 19वीं शताब्दी में यूरोप की अर्थव्यवस्था और राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन थी, जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम लिया जाने लगा तथा औद्योगिक संगठन में परिवर्तन हुआ। घरों में उद्योग चलाने की अपेक्षा कारखानों में काम होने लगा। औद्योगिक क्रांति एक दूसरे से संबंधित तीन क्षेत्रों – आर्थिक संगठन, तकनीकी एवं व्यापारिक ढांचे में उत्पन्न विकास का परिणाम है।[1]

औद्योगिक क्रांति की शुरूआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई, इसका मुख्य कारण था कि 18वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड ने विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित कर लिया था। वाणिज्यवाद के परिणामस्वरूप प्रचुर मात्रा में इंग्लैंड में धन जमा हो गया था। अन्य उपनिवेशों से प्राप्त धन मुख्यतः भारत की लूट ने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के लिए प्रमुख रूप से उत्प्रेरक कार्य किया। इतिहासकार रजनीपाम दत्त ने 'आज का भारत' में लिखा है, ''यदि प्लासी की लूट का माल और भारत की सम्पदा इंग्लैंड की ओर उन्मुख न हुई होती तो मेनचेस्टर, पेंसले और लंकाशायर की सूती मिलें नष्ट हो जाती तथा जेम्सवार, आर्कराइट, कार्टराइट तथा क्राम्पटन जैसे अविष्कारकों के अविष्कार समुद्र में फेंक दिए जातें।''[2]

औद्योगिक क्रान्ति के बाद प्रत्येक औद्योगिक देश के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह अपने राष्ट्रीय बाजार को संरक्षित करे। अन्य देशों की निर्मित वस्तुओं पर भारी कर लगाकर राष्ट्रीय उत्पादनों को महत्व दिया जाने। परंतु उत्पादित माल को जब अपने ही देश में खपाना मुश्किल हो गया, तब अविकसित एवम् पिछड़े देशों में मण्डियों एवम् बाजारों की तलाश करनी पड़ी ओर बाजारों की आवश्यकता ने सरकारों को उपनिवेश प्राप्ति की ओर प्रेरित किया।[3]

इंग्लैंड में आई औद्योगिक क्रान्ति से इंग्लैंड में आर्थिक परिवर्तन आए जिन्हें भौतिक परिवर्तन भी कहा जा सकता है। इन भौतिक परिवर्तनों से समाज में भी परिवर्तन दिखाई दिए तथा नए वर्गों का उदय हुआ। इस नए वर्ग की अपनी राजनीतिक आवश्यकताएं एवम् उद्देश्य थे।

18वीं शताब्दी तक ब्रिटिश संसद में केवल भूमिपतियों का ही प्रभाव था परन्तु औद्योगिक क्रान्ति ने जिस नए वर्ग को जन्म दिया, वह यह सहन नहीं कर पाया कि राजनीति या संसद में भूमिपतियों का ही वर्चस्व रहे। इस प्रकार औद्योगिक क्रान्ति से पनपे वर्गों ने ब्रिटिश संसद को भूमिपतियों के हाथो से मुक्त कराने का प्रयास किया तथा इंग्लैंड में होने वाले संसदीय सुधार औद्योगिक क्रान्ति के ही परिणाम स्वरूप सम्भव हुए। औद्योगिक क्रान्ति ने न केवल इंग्लैंड की राजनीति पर ही प्रभाव डाला अपितु भारतीय राजनीति को भी प्रभावित किया।[4]

औद्योगिक क्रान्ति ने ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादन को उच्चतम शिखर पर पहुंचा दिया जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन की आर्थिक प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया। इस परिवर्तन से उपनिवेशवादी व्यवस्था में भी परिवर्तन आना स्वभाविक था। ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा भारतीय हस्तकला की वस्तुओं के इंग्लैंड और यूरोप में निर्यात अथवा लगान की प्रत्यक्ष लूट से ब्रिटेन के उभरते वर्ग को कोई लाभ नहीं था। उन्हें तो अपने दिन–प्रतिदिन बढ़ते हुए उत्पादन की खपत के लिए विदेशी बाजारों की आवश्यकता थी और भारत जैसा विशाल और अधिक जनसंख्या वाला देश उनके लिए एक जबरदस्त आकर्षण था।[5] अंतः ब्रिटिश सरकार ने कम्पनी पर दबाव डाला कि भारत में प्रमुख क्षेत्रों पर अधिकार जाए जिससे कि ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग को कच्चे माल का स्त्रोत और तैयार माल के लिए बाजार उपलब्ध हो सके। कम्पनी ने पहले ही युद्धों द्वारा भारत में साम्राज्य विस्तार का कार्य आरम्भ कर दिया था परन्तु ब्रिटिश सरकार के कम्पनी पर बढ़ते दबाव के कारण कम्पनी ने सहायक सन्धि व व्यपगत के सिद्धान्त का सहारा लेते हुए भारतीय क्षेत्रों को हस्तगत करने का प्रयास किया।[6]

भारतीय क्षेत्रों पर विस्तार के लिए कम्पनी पर दबाव : –

लार्ड वैलेजली ने भारतीय क्षेत्रों पर विस्तार के लिए एक नई नीति का अनुसरण किया जिसको सहायक सन्धि कहा जाता है। वैलेजली ने देशी राज्यों के साथ एक विशेष प्रकार की सन्धि करना आरम्भ किया इसके द्वारा वैलेजली ने कम्पनी के साम्राज्य का विस्तार किया, भारतीय नरेशों के दरबार और उनकी राजनीति में अंग्रेजों के प्रभाव को बढ़ाया।

इससे जिन क्षेत्रों के साथ सहायक सन्धि की गई थी उन क्षेत्रों को कच्चे माल के स्त्रोत रूप में प्रयोग किया जाने लगा व उन क्षेत्रों को मण्डी का रूप दे दिया। इसी प्रकार व्यपगत के सिद्धांत द्वारा डलहौजी ने अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया तथा उन क्षेत्रों को अपने आर्थिक हितों के लिए उपयोग में लाना शुरू कर दिया। तथा पंजाब जो कि कच्चे माल का बहुत बड़ा स्त्रोत था, पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कम्पनी पर दबाव डाला।[7]

औद्योगिक वर्ग और ब्रिटिश सरकार के कुछ कार्य : –

औद्योगिक पूंजीपति कालांतर में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के प्रधान तत्व के रूप में उभरे। इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारत में अपनी विजय का आनन्द लेना शुरू ही किया था कि ब्रिटेन के उभरते हुए नए औद्योगिक वर्ग ने इसकी व्यापारिक प्रभुसत्ता को को सीमित करने तथा इसे ब्रिटिश संसद के अधीन करने का आंदोलन आरम्भ कर दिया।[8] प्रारम्भिक पूंजीवाद के व्यापारवादी सिद्धान्तों की जगह पर औद्योगिकरण के युग में स्वतन्त्र व्यापार सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना आवश्यक हो गया। इस परिवर्तित परिस्थिति में आवश्यक था कि भारत में पुराने एकाधिकारवाद की जगह एक स्वतन्त्र व्यापार का निर्माण किया जाए। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ था कि ईस्ट कम्पनी की पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए।[9] अतः ब्रिटिश सरकार से यह अनुरोध किया गया कि वह भारत में कम्पनी की व्यवस्था पर नए सिरे से विचार करे और समयानुसार इसमें परिवर्तन करे। ईस्ट इंडिया कम्पनी के खिलाफ एक संगठित आन्दोलन शुरू हुआ इसमें एक औद्योगिक वर्ग द्वारा यह मांग की गई कि भारत में सबको घुसने की छुट मिले।

1833 के बाद कम्पनी का कोई भी व्यापारिक कार्य नहीं रह गया इस प्रकार यह एक पूर्ण प्रशासकीय संस्था बन गई। अंततः 1813 में कम्पनी को भारत में व्यापार करने के एकाधिकार से वंचित कर दिया गया। 1833 में कम्पनी की सभी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां पर रोक लगा दी गई और भारत के सभी शहर,

कस्बे, गांव, जंगल, खानें, कृषि, उद्योग तथा जनसंख्या का विशाल मानव–समुदाय ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश पूंजीपतियों के मुक्त प्रयोग के लिए खुले छोड़ दिए गए।[10]

भारत के आर्थिक शोषण को इस नए उद्देश्य के अनुसार संभव बनाने के लिए एक नए राजनीतिक एवम् आर्थिक ढांचे की आवश्यकता थी। जहां पहले चरण में भारत के राजनीतिक और आर्थिक ढ़ांचे में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं किए गए, वहां दूसरे चरण में ये परिवर्तन अनिवार्य हो गए ताकि ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में भारत अपनी नई भूमिका निभा सके।[11] भारत के सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए मुक्त व्यापार की नीति तथा ब्रिटिश पूंजीपतियों और व्यापारियों को भारत में आने के अतिरिक्त जमींदारी और रैयतवारी व्यवस्थाओं के माध्यम से लगान इक्ट्ठा करने के तरीकों में भी परिवर्तन किए गए। प्रशासन को और अधिक व्यापक बनाया गया। कर उगाहने, कानून और व्यवस्था को कड़ा करने तथा व्यापार मांगों को सुरक्षित रखने की दिशा में कई कदम उठाए गए। प्रशासन को और अधिक व्यापक बनाया गया। कर उगाहने, कानून और व्यवस्था को कड़ा करने तथा व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखने की दिशा में कई कदम उठाए गए। प्रशासन की पहुंच गांवों तक हो गई ताकि ब्रिटिश वस्तुए छोटे कस्बों और गांवों तक पहुंच सके और वहां से निर्यात योग्य कच्चा माल इक्ट्ठा किया जा सके। राज्य के कानूनी ढांचे में भी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई ताकि यह व्यापारवादी, पूंजीवादी सम्बंधों की रक्षा कर सके। नए प्रशासन, न्याय की व्यवस्था तथा ब्रिटिश व्यापारिक संगठनों के लिए काफी बड़ी मात्रा में पढ़े–लिखे बाबुओं की आवश्यकता थी। अतः 1813 के बाद आधुनिक पश्चिमी शिक्षा आरम्भ की गई जिसे 1833 के बाद और अधिक विकसित किया गया।[12]

प्रभाव : –

औद्योगिक क्रान्ति के कारण कम्पनी पर दबाव बढ़ा कि कम्पनी भारतीय क्षेत्रों पर और अधिक राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करे ताकि इंग्लैंड इनसे कच्चा माल प्राप्त कर सके और अपने तैयार माल के लिए बाजार के रूप में इस्तेमाल कर सके। कम्पनी ने युद्धों द्वारा पहले से ही भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, साथ ही सहायक सन्धि द्वारा कम्पनी ने भारत के कई उपजाऊ और आबादी वाले क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया।[13]

इस प्रकार सहायक सन्धि से प्राप्त इन क्षेत्रों से कम्पनी का भूराजस्व बढ़ा, इन्हें बिना किसी खर्च के सेना प्राप्त हुई तथा कच्चे माल का स्त्रोत और तैयार बाजार उपलब्ध हो गया। पंजाब जो कि उपजाऊपन और जनसंख्या की दृष्टि से धनी था को हस्तगत करने के लिए कम्पनी पर लन्दन से दबाव पड़ा और अन्त में 1849 में पंजाब को भी कम्पनी ने अपनी अधीन कर लिया। डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के कारण भी भारत के बहुत से मुख्य प्रदेशों पर कम्पनी का अधिकार हो गया था।

औद्योगिक क्रान्ति के कारण जहां एक तरफ कम्पनी पर भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का दबाव था, वहीं स्वयं कम्पनी की शक्तियों को भी नियंत्रित करने का प्रयास औद्योगिक वर्ग द्वारा किया जा रहा था। जैसे ही कम्पनी भारत में प्रादेशिक शक्ति बनी, वैसे ही इंग्लैंड में इस सवाल को लेकर तीव्र संघर्ष छिड़ गया कि भारतीय उपनिवेश किसके हितों या स्वार्थों की पूर्ति करेगा। 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट और ऐडम स्मिथ के पुस्तक ''वैल्थ ऑफ नेशन्स'' में व्यक्त विचारों के आधार पर उभरते हुए नए विचारों के आधार पर

International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

ब्रिटेन के उभरते हुए औद्योगिक वर्ग ने 1813 में कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके मुक्त व्यापार के द्वार खोल दिए। 1833 के एक्ट से कम्पनी की सभी व्यापारिक गतिविधियां बंद कर दी गई इसे पूर्णतः एक राजनीतिक संस्था बना दिया गया।[14]

औद्योगिक क्रान्ति ने भारतीय क्षेत्रीय उद्योगों को बर्बाद कर दिया। इंग्लैंड में मशीनों द्वारा निर्मित सस्ते सामान के आगे भारत का हस्तनिर्मित और महंगा सामान टिक नहीं पाया और अंततः भारतीय क्षेत्रीय उद्योगों का पतन हो गया। इंग्लैंड में दस्तकारी तबाह हुई तो उसकी वजह मशीनों के उद्योग धंधे चालू हुए, लेकिन हिन्दुस्तान में लाखों कारीगर और जुलाहे तबाह हुए तो उनके साथ नए उद्योग धन्धे नहीं बढ़े।

वाणिज्यवादी काल में भारत के द्वारा निर्यात की जाने वाली तैयार वस्तुएं हुआ करती थी जो कि भारतीय हस्तशिल्पियों द्वारा तैयार की गई होती थी परन्तु औद्योगिक क्रान्ति के कारण भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का स्वरूप बदल गया। भारत से कच्चा माल कपास, जूट तथा नील आदि व्यापारी द्वारा ले जाया गया। 1813 से पूर्व जहां भारत सदैव निर्मित वस्तुओं का निर्यातक तथा मूल्यवान धातुओं और विलास उत्पादनों का आयातक था वहीं बाद में कृषि सम्बंधी कच्चे सामान तथा खाद्य पदार्थों का निर्यातक व निर्मित सामान का आयातक बन गया।

14. ताराचन्द, – 'भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास' भाग–1, पृ0 –246

भारत में कृषि उत्पादों के सम्बंध में भी परिवर्तन हुआ, जहां पहले खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता था वहीं इंग्लैंड में स्थापित कारखानों की मांग के कारण भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण किया गया।[15] खाद्यान्न फसलों की जगह नकदी फसले कपास, नील, जूट, चाय, काफी, अफीम व तिलहन आदि फसलें उगाई जाने लगी।

निष्कर्ष : –

औद्योगिक क्रान्ति जिसने कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया न केवल इंग्लैंड बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति पर भी समान रूप से प्रभाव डाला। औद्योगिक क्रान्ति ने भारतीय उद्योग धन्धों को नष्ट कर दिया, कृषि का व्यवसायीकरण किया तथा इसके आयात व निर्यात के स्वरूप में परिवर्तन किया। औद्योगिक क्रान्ति ने एक नए वर्ग औद्योगिक वर्ग को जन्म दिया जिसके अपने राजनीतिक उद्देश्य एवं आवश्यकताएं थी। इस औद्योगिक वर्ग ने ब्रिटिश संसद पर कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए दबाव डाला। साथ ही ब्रिटिश संसद द्वारा कम्पनी पर दबाव डाला गया कि वह भारतीय क्षेत्रों को अपने हस्तगत करे ताकि इंग्लैंड को कच्चे माल का स्त्रोत और तैयार माल के लिए मण्डी के रूप में उपनिवेश प्राप्त हो सके।

Footnots :

1. साउथगेट, जी, डब्लू – इंग्लिश इकोनिमिक हिस्ट्री,, पृ0 155
2. पामदत्त, रजनी, ''आज का भारत'' पृ0 – 428
3. थोमसन डेविड, – यूरोप सिन्स नेपोलियन, पृ0 – 113
4. साउथगेट, जी, डब्लू – इंग्लिश इकोनिमिक हिस्ट्री, पृ0 – 157
5. थोमसन डेविड, – यूरोप सिन्स नेपोलियन, पृ0 – 114
6. विपिन, चन्द्रा, ''भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्‌भव और विकास'' पृ0–84
7. रोबेटर्स पी. ई., ''इण्डिया अण्डर वैलजली'', पृ0 – 136
8. सत्या, एम, राय – 'भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद', पृ0 –23

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

9. विपिन, चन्द्र – 'भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्‌भव और विकास', पृ0 –56
10. सत्या, एम. राय, – 'भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद', पृ0 –27
11. मिश्र गिरीश – 'आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास', पृ0 –37
12. सत्या, एम. राय, – 'भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद', पृ0 –24
13. रोबेटर्स पी.ई., – 'इण्डिया अण्डर वैलजली', पृ0 – 138
15. डिग्बी विलियम – 'प्रोस्पेरस ब्रिटिश इण्डिया' पृ0 – 32

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. चन्द्र विपिन – भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्‌भव और विकास – द मैकमिलन कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, प्रथम संस्करण, नई दिल्ली – 1997
2. डिग्बी, विलियम – प्रास्पेरस ब्रिटिश इण्डिया, – सागर पब्लिकेशन, नई दिल्ली – 1969
3. ताराचन्द – भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास – भाग–1 प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली – 1965
4. थोमसन डेविड – यूरोप सिन्स नेपोलियन – ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सीटी प्रैस, लंदन – 1967
5. पामदत्त, रजनी – आज का भारत, – द मैकमिलन कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली–1983
6. मिश्र गिरीश – आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास – ग्रन्थ शिल्पी पाईवेट लिमिटेड, प्रथम संस्करण नई दिल्ली – 1997
7. एम.राय. सत्या – भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद – हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
8. रोबर्टस पी.ई. – इण्डिया अण्डर वैलजली – पापुलर बुक डिपो – बाम्बे – 1959
9. साउथगेट, जी, डब्लू, – इंग्लिश इकोनिमिक हिस्ट्री – ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, लंदन – 1976